अपीलीय आपराधिक

एस. एस. संधावालिया, न्यायमूर्ति और बी. एस. ढिल्लों, न्यायमूर्ति.

बीरबल आदि- अपीलकर्ता।

बनाम

राज्य, - उत्तरदाता।

1968 की आपराधिक अपील संख्या 1006।

20 मई, 1971।

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V) - धारा 423 - भारतीय दंड संहिता (1860 का XLV) - धारा 34 के साथ एक ठोस अपराध का आरोप लगाया गया आरोपी - ट्रायल कोर्ट धारा 34 को लागू नहीं करता है लेकिन आरोपी को मूल अपराध के लिए दोषी ठहराता है - ऐसी दोषसिद्धि के खिलाफ अभियुक्त द्वारा अपील - राज्य द्वारा कोई अपील नहीं - अपीलीय न्यायालय – क्या अपीलीय न्यायालय धारा 34लागू कर सकता है.

निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एक महत्वपूर्ण अपराध नहीं है और इस धारा के तहत बरी होने जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। सामान्य इरादा आमतौर पर होता है, यदि हमेशा आसपास के तथ्यों से एक अनुमान नहीं होता है। सामान्य इरादे की अनुपस्थिति या उपस्थिति के बिंदु पर एक खोज अनिवार्य रूप से तथ्य की खोज की प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए

कोई कारण नहीं है कि धारा 34 के बारे में इस तरह का निष्कर्ष अपीलीय न्यायालय के दायरे से बाहर होना चाहिए, जबकि तथ्य के अन्य सभी समान निष्कर्ष इसके दायरे में हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 (1) (बी) स्पष्ट रूप से अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में एक निष्कर्ष को बदलने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय जब दोषसिद्धि के खिलाफ अपील से मुक्त हो जाता है तो वह सबूतों पर विचार कर सकता है और संभावनाओं पर विचार कर सकता है। यह सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किए गए सबूतों को स्वीकार कर सकता है और उनके द्वारा स्वीकार किए गए सबूतों को खारिज कर सकता है। दोषसिद्धि से अपील की सुनवाई करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्ति पर एक शर्त यह रखी गई है कि वह बरी करने के फैसले को तब तक नहीं पलट सकता जब तक कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत इसके खिलाफ अपील न हो। यह प्रतिबंध क़ानून का एक प्राणी है। यह एक तकनीकी नियम है जो अपीलीय अदालत द्वारा एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि की रिकॉर्डिंग को रोकता है, जिसे केवल उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ निर्देशित अपील में एक विशिष्ट अपराध से बरी कर दिया गया है। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब किसी ठोस अपराध के आरोप में बरी किए जाने का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया हो। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एक दंडनीय प्रावधान नहीं है और यह एक महत्वपूर्ण अपराध नहीं है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप किसी को बरी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलीय अदालत की शक्ति को आम इरादे की अनुपस्थिति के बारे में एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने की और मूल आरोप पर बरी करने के फैसले को पलटने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता

है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के आवेदन या अन्यथा के संदर्भ में बरी किए जाने के फैसले को पलटने की रोक दूर-दूर तक आकर्षित नहीं होती है। इसलिए जब किसी अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़े गए मूल अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है, और ट्रायल कोर्ट धारा 34 को लागू नहीं मानता है, लेकिन आरोपी को वास्तविक अपराध के लिए दोषी ठहराता है, तो अपीलीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 के तहत ऐसी सजा के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए, धारा 34 के प्रावधानों को लागू कर सकती है, भले ही राज्य द्वारा कोई अपील न हो। हालांकि यह समान रूप से स्वयंसिद्ध है कि जहां आम इरादे की अनुपस्थिति के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप एक ठोस आरोप पर बरी हो जाता है, इसे धारा 423 (1) (बी) के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है।

(पृष्ठ 8 से 11)

माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया द्वारा 4 दिसंबर, 1969 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंडपीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और 20 मई, 1971 को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद इसे एकल पीठ को वापस भेज दिया।

इस मामले का अंतिम निर्णय 24 मई, 1971 को एकल पीठ द्वारा किया गया।

श्री अमर नाथ अग्रवाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार के दिनांक 14 अक्तूबर, 1968 के आदेश से अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए अपील।

हरप्रसाद और एम.एक. सरपाल, के लिए डॉक्टर ए.एस. अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए

हरि मित्तल, प्रतिवादी की ओर से हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता

आदेश

एस.एस. संधावालिया, न्यायमूर्ति, पीठ के निर्णय के लिए तैयार किए गए कानून का प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में है:-

> "क्या एक अपीलीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 (एक) (बी) के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर विचार करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने की हकदार है, जहां ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अन्यथा माना है (हालांकि आरोपी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ एक महत्वपूर्ण अपराध का आरोप लगाया गया था) और राज्य इस तरह के निष्कर्ष के खिलाफ अपील के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा।

यह केवल उपर्युक्त कानूनी प्रश्न से संबंधित तथ्यों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त होगा। मनफूल अपीलकर्ता और उसके बेटे बीरबल अपीलकर्ता पर हिसार में सत्र न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त

आरोप पर दोनों को बरी कर दिया, लेकिन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 1 के तहत मामूली अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों पर स्पष्ट रूप से पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 इस मामले में लागू नहीं हुई थी।

(2) राम सरूप और श्रीमती नरैनी नाम की एक महिला उनके गांव के बस्ती राम नाम से खेती की जमीन का एक टुकड़ा लेकर आई थी। इसके बाद, हालांकि, उन्होंने बीरबल अपीलकर्ता को खेती में भागीदार के रूप में शामिल किया ताकि उसके खेत के जानवरों का उपयोग किया जा सके। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि बीरबल अपीलकर्ता चने की कृषि उपज और चारे को कटाई के बाद राम सरूप मृतक के घर ले जाएगा और इसे सहमति के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। 2 मई, 1968 को राम सरूप की मृत्यु हो गई, श्रीमती नरैनी और बीरबल अपीलकर्ता ने उनके बीच चने की फसल को विधिवत रूप से साझा किया और इसे अपने-अपने घरों में ले गए। हालांकि, उसमें से शेष चारा खेत में पड़ा रहा और बाद में विभाजित किया जाना था। हालांकि, 3 मई, 1968 को, बीरबल अपीलकर्ता ने खेतों में पड़े पूरे चारे को अपने घर ले जाया। इस बात का पता चलने पर राम सरूप मृतक अपनी पत्नी पी. डब्ल्यू. शरबती के साथ शाम के समय बीरबल अपीलकर्ता के घर गया और उसके साथ पूरा चारा निकालने के लिए प्रार्थना की, जिसमें उसके अनुसार, मृतक और श्रीमती नरैनी के अविभाजित शेयर शामिल थे। जब उपरोक्त विरोध किया गया तो मनफूल अपीलकर्ता भी घर में

मौजूद था और एक तरफ दो अपीलकर्ताओं और दूसरी तरफ मृतक और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ। भगवाना और शिव करण पी. डब्ल्यू. जो कोर्ट-यार्ड के बगल वाली गली में गुजर रहे थे, हंगामे से आकर्षित हुए और उनकी उपस्थिति में बीरबल अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से राम सरूप मृतक के सिर पर लाठी का वार किया, जिसके मिलने पर वह तुरंत जमीन पर गिर गया। इसके बाद दोनों अपीलकर्ताओं ने मृतक को चार या पांच और चोटें दीं। पी. डब्ल्यू. शिव करण और भगवाना ने बीच बचाव किया और मृतक को और चोट से बचाया, लेकिन घटना के लगभग एक घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद पी.डब्ल्यू. शरबती के बयान पर अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

(3) जैसा कि मेरे द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत संदर्भ क्रम से स्पष्ट है, डीएसअभियोजन मामले 1 को लगभग पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। हालांकि, जिस मुद्दे को डिवीजन बेंच के पास भेजा गया है, वह मनफूल अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति है। इस अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा 304, भाग 1 के तहत उसकी दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इस तर्क के लिए भरोसा पहले चिकित्सा गवाही पर रखा गया था, जो इसलिए कुछ विस्तार से नोटिस के योग्य होगा। 4 मई, 1968 को डा सांगवान ने राम सरूप के शरीर का शव परीक्षण किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं -

(1) खोपड़ी के ओसीसीपिटल हड्डी क्षेत्र के दाईं ओर हड्डी तक गहरा घाव

"$\mathbf{1^1/2}$ **x** $\mathbf{1^1/2}$" है।

(2) चोट नंबर 1 के समानांतर खोपड़ी के बाईं ओर ओसीसीपिटल क्षेत्र पर हड्डी तक 2 "x 2" गहरा घाव है।

(3) दाहिनी कलाई के पीछे 4 "x 2" गहरा घाव है।;

(4) दाएं कंधे के सामने 4 "x 3" गहरा घाव है।;

(5) बाएं इलियाक क्षेत्र पर 4"x2|" गहरा घाव है।;

(6) बाएं अग्रभाग के बाहरी हिस्से पर 5 "x 3" गहरा घाव है।;

(7) पीठ के बाईं ओर 6 "x2" गहरा घाव है।

इस गवाह ने कहा कि मृतक की मौत सदमे और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप कई चोटों का परिणाम थी और इन सभी चोटों को प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त बताया गया था। गवाह ने यह भी कहा कि चोट नंबर 1 और 2 है। मृतक के सिर पर सामूहिक रूप से प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे।

(4) उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि मृतक के सिर पर सात चोटों में से केवल दो खतरनाक चरित्र के थे, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः मृत्यु हो सकती थी, जबकि अन्य पांच केवल शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोट लगी थीं। इसके साथ ही यह तथ्य भी है कि मनफूल अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई चोट के बारे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट थे। जबकि सिर पर पहला

झटका स्पष्ट रूप से बीरबल अपीलकर्ता को दिया गया था, उसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चला कि दोनों अपीलकर्ता ने मनफूल अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट चोट दिए बिना मृतक के शरीर पर बाकी चोटें पहुंचाईं। इस प्रकार इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि मृतक के सिर पर दूसरी चोट इस अपीलकर्ता द्वारा किसी भी आघात का परिणाम थी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष भी उसी प्रभाव का है और इन शर्तों में है: –

"चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, चोटें संख्या 1 और 2 सामूहिक रूप से मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थीं। रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों आरोपियों में से किसने मृतक के सिर पर दूसरी चोट पहुंचाई"

मेडिकल गवाही और उपरोक्त निष्कर्ष पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, जिसे अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं उठाया गया था, यह तर्क दिया गया था कि इस संदर्भ में जब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को विशेष रूप से लागू नहीं माना गया है और चूंकि अपीलकर्ता को किसी विशिष्ट सिर की चोट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, इसलिए उसे धारा 304 भाग I, भारतीय दंड संहिता। के तहत मूल अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(5) तथापि, तथ्यों पर विस्तृत विचार करने के बाद, मैं इस सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकला कि दोनों अपीलकर्ताओं को चोट पहुंचाने के समान इरादे से किया गया था जो

उन्होंने मृतक को दिया था और ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकालने में गलती की थी। फिर भी यह तर्क दिया गया कि दोनों अपीलकर्ताओं पर विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया था, और ट्रायल कोर्ट ने इस पहलू को देखने के बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत आरोप से बरी कर दिया था। यह तर्क दिया गया था कि राज्य द्वारा सामान्य इरादे की अनुपस्थिति के निष्कर्ष के खिलाफ और परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। वकील ने अपने रुख को दोहराया कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू नहीं होती है, पवित्र है और वर्तमान अपील में इसे बाधित नहीं किया जा सकता है और अपीलीय अदालत को दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने से रोक दिया गया था। यह इस विवाद की वैधता है जो अब मुद्दे में है।

(6) इस बात पर ध्यान दिया गया कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हैर्स प्रसाद अपने मुवक्किलों के पक्ष में कानूनी प्रस्ताव को प्रचारित करने में आधे-अधूरे मन से दिखाई दिए। हमारे समक्ष यह विवादित नहीं था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 दंडनीय प्रावधान नहीं है। इसे अध्याय II में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 10, जिसमें "सामान्य स्पष्टीकरण" शीर्षक है। यह एक महत्वपूर्ण अपराध पैदा नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है, जो अब चुनौती से परे है। बी में। एन श्रीकांतिया और एक अन्य मैसूर

राज्य, [1]उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार माना कि: -

> "धारा 34 केवल साक्ष्य का एक नियम है और एक महत्वपूर्ण अपराध नहीं बनाता है। इसका मतलब है, कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर एक काम करते हैं, तो संयुक्त रूप से यह वैसा ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से किया था"

उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि जयकृष्णदास मनोहरदास देसाई और एक अन्य बनाम

बॉम्बे राज्य[2] मामले में निम्नलिखित शब्दों में:-की गई है।

> "धारा 34 अपराध पैदा नहीं करती है; यह केवल अपराधियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है।

मैं यह नोटिस करूंगा कि उपरोक्त निर्णय को स्वयं श्री हर प्रसाद द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है।

(7) यद्यपि न्यायिक पीठ के समक्ष प्रश्न असामान्य घटना नहीं है और आपराधिक अपीलों में अक्सर उठता है, फिर भी इस बिंदु पर सीधे प्रभाव डालने वाले अधिकार की तीव्र कमी प्रतीत होती है। यह मामला जो चारों ओर से विचाराधीन प्रतीत होता है, वह उमराव सिंह और अन्य बनाम

[1] ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 672.

[2] ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 889.

मध्य प्रदेश राज्य[3] के मामले में एकल पीठ का निर्णय है । उस मामले में तीन व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा, 325 और 352 के तहत संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू नहीं थी और दो याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि तीसरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के तहत दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही में एक समान आपत्ति ली गई थी कि चूंकि याचिकाकर्ताओं कोभारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत रचनात्मक दायित्व का दोषी ठहराया गया था, और प्रत्येक के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत हमलों के बारे में सबूत का अभाव था। इसलिए, उच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधान को लागू नहीं कर सका। इस तर्क को खारिज करते हुए शिव दयाल, न्यायमूर्ति. ने इस प्रकार टिप्पणी की है: -

"एक अपीलीय अदालत या एक पुनरीक्षण अदालत एक दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए धारा 34 * को लागू करने की हकदार है। यह सच है कि धारा 34 नीचे के न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की गई थी। याचिकाकर्ताओं को दंड संहिता की धारा 325 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था और बरी किए जाने के खिलाफ अपील के अभाव में मैं उन्हें उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन मैं निश्चित रूप से दंड संहिता की धारा 323 के तहत

[3] ए सीआर 1961 एम.पी.

> अपराध के लिए उनके दायित्व के संबंध में धारा 34 लागू कर सकता हूं। 'धारा 34 को बरी करना' गलत है क्योंकि धारा 34 एक महत्वपूर्ण अपराध नहीं बनाती है। इसलिए उमराव सिंह और कुंवरलाल की सजा में बदलाव आएगा"

श्री हर प्रसाद स्वीकार करते हैं कि अनुसंधान के बावजूद वह सीधे या एनोलॉजी के माध्यम से इसके विपरीत किसी भी प्राधिकरण का हवाला देने में असमर्थ हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर सीधे असर डालने वाला एकमात्र निर्णय स्पष्ट रूप से पीठ को भेजे गए प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने के पक्ष में है।

एक. –.

(8) प्राधिकरण के अलावा, सिद्धांत रूप में मुद्दा भी मुख्य रूप से प्रतिवादी राज्य के पक्ष में भारित प्रतीत होता है। एक बार जब यह सत्यापित हो जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34, एक उप-मौलिक अपराध का गठन नहीं करती है, तो ऐसा लगता है कि तार्किक रूप से इसका पालन किया जाता है कि इस धारा के तहत बरी होने जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। धन उधार लेना। शिव दयाल, न्यायमूर्ति की अभिव्यक्ति में, "धारा 34 के तहत बरी होना" शब्द का उपयोग करना एक गलत धारणा है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत बरी किए जाने के फैसले को पलटने का काल्पनिक विवाद संभवत: पैदा नहीं हो सकता। यदि उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 साक्ष्य का एक नियम है, तो साक्ष्य के नियम के तहत बरी होने की कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि बरी करने के निष्कर्ष को केवल एक महत्वपूर्ण अपराध के आरोप के संदर्भ में देखा जाता है। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एक महत्वपूर्ण अपराध नहीं है, इसलिए संभवतः इसके तहत कोई बरी नहीं किया जा सकता है।

(9) यह भी उतना ही अच्छी तरह से तय है कि; किसी व्यक्ति के इरादे को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत प्राप्त करना असंभव नहीं तो मुश्किल है।और ज्यादातर मामलों में आरोपी व्यक्ति के कार्य या आचरण या उससे संबंधित अन्य परिस्थितियों से सामान्य इरादे का अनुमान लगाया जाना चाहिए। इसलिए, आम इरादा, आमतौर पर, यदि मामले के आसपास के तथ्यों से हमेशा एक अनुमान नहीं होता है, तो सामान्य इरादे की अनुपस्थिति या उपस्थिति के बिंदु पर एक खोज अनिवार्य रूप से तथ्य की खोज की प्रकृति का हिस्सा होती है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि धारा 34 के बारे में ऐसा निष्कर्ष अपीलीय न्यायालय के दायरे से बाहर होना चाहिए, जबकि तथ्य के अन्य सभी समान निष्कर्ष इसके दायरे में हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 (1) (बी), स्पष्ट रूप से अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में एक निष्कर्ष को बदलने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय जब दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करता है तो वह सबूतों पर विचार कर सकता है और संभावनाओं पर विचार कर सकता है। यह सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किए गए सबूतों को स्वीकार कर सकता है और उनके द्वारा स्वीकार किए गए सबूतों को खारिज कर सकता है। इस संबंध में संदर्भ शेर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश

राज्य का दिया जा सकता है।,[4]अत, यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423(1)(बी) के तहत अपीलीय न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियों में उनके दायरे में समान मंशा के अस्तित्व या उसकी अनुपस्थिति के बारे में निष्कर्ष को बदलने का अधिकार शामिल होगा।

(10) दोषसिद्धि से अपील की सुनवाई करते समय अदालत की शक्ति पर यह अधिकार है कि वह बरी करने के फैसले को तब तक नहीं पलट सकता जब तक कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत इसके खिलाफ अपील न हो। यह बार क़ानून का एक प्राणी है। यह एक तकनीकी नियम है जो अपीलीय अदालत द्वारा एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि की रिकॉर्डिंग को रोकता है, जिसे केवल उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ निर्देशित अपील में एक विशिष्ट अपराध से बरी कर दिया गया है। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब किसी ठोस अपराध के आरोप में बरी किए जाने का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया हो। जोर देने के लिए अब यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एक दंडात्मक प्रावधान नहीं है और एक महत्वपूर्ण अपराध का गठन नहीं करती है। इसके परिणामस्वरूप किसी को बरी नहीं किया जा सकता। इसलिए आम इरादे की अनुपस्थिति के बारे में एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने की अपीलीय अदालत की शक्ति को एक ठोस आरोप पर बरी करने के फैसले को पलटने के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के आवेदन या अन्यथा के संदर्भ में बरी किए जाने के फैसले को पलटने की

[4] ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1412.

रोक दूर-दूर तक आकर्षित नहीं होती है।

(11) हालांकि, यह क्यू समान रूप से स्वयंसिद्ध है कि सामान्य इरादे की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप एक ठोस आरोप पर बरी हो जाता है, लेकिन इसे धारा 423 (एक) (बी) के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में उलट नहीं किया जा सकता है। फिर भी हालांकि इस तरह के बरी होने के खिलाफ निर्देशित अपील को छोड़कर इस तरह के बरी होने को उलट नहीं किया जा सकता है, अपीलीय अदालत इस तथ्य को रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू थी, भले ही यह नीचे की अदालत द्वारा लागू नहीं किया गया था। एक संदेह व्यक्त करने की मांग की गई थी कि ऐसे मामलों में जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है, और कुछ आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है (और राज्य द्वारा इस बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है) और अन्य को दोषी ठहराया गया है, तो दोषियों द्वारा दायर अपील में अपीलीय न्यायालय के लिए यह असंगत होगा। सामान्य इरादा जो ट्रायल कोर्ट के विपरीत हो सकता है। यह तर्क दिया जाना चाहिए कि धारा 423 (1) (ए) अप्रत्यक्ष रूप से और संयोग से बरी किए गए व्यक्तियों के खिलाफ मामले पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय के खिलाफ एक रोक पैदा करेगी। इस विवाद का पूरा जवाब सुंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य[5] में न्यायमूर्ति की टिप्पणियों

[5] ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1211.

द्वारा प्रदान किया गया है । (9) जहां उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में एक समान तर्क को पीछे हटा दिया:

"वास्तव में, एक अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय को अप्रत्यक्ष रूप से और संयोग से एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए सबूतों पर विचार करना होता है, जिसे कई मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था, जहां वह सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके समक्ष अपील से निपट रहा है, जिन्हें उसी मुकदमे में दोषी ठहराया गया था और ऐसा करने में, उच्च न्यायालय और यहां तक कि यह न्यायालय कभी-कभी अपने अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को दर्ज करता है कि बरी किए गए व्यक्तियों के खिलाफ सबूत कमजोर या असंतोषजनक नहीं था और यह कि और बरी किए जाने को इस अर्थ में अनुचित माना जा सकता है। बिम्बाधर प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य के फैसले के अनुसार यह असंतोषजनक है और इस अर्थ में बरी किए जाने को अनुचित माना जा सकता है।[6]

(12) इस चर्चा के दौरान हमारा यह विचार है कि पीठ को भेजे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में लौटाया जाना चाहिए।

बी.एस. ढिल्लों,न्यायमूर्ति..- मैं सहमत हूँ।

[6] ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 469.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
पानीपत, हरियाणा